

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील संख्या 07/11 उषा कुंवर बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य आदेश</p> <hr/> <p>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 195 दिनांक 13.1.11 के विरुद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉत्र दल (प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा एवं अंचलाधिकारी, मढ़ौरा) के उषा कुंवर, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 86/07, ग्राम-कर्णकुदरिया, पंचायत-कर्णकुदरिया, थाना-प्रखंड-मशरक की दूकान की जांच की गयी। जांच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जांच नहीं की जा सकी तथा मॉगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त 	



कागजात जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3445 दिनांक 8.12.10 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जाँच की तिथि को डॉ० से दिखाने हेतु विक्रेता गोपालगंज गई थी। उनके विरुद्ध अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में या आदेश में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। जो भी आरोप लगाया गया है, वे सभी गलत सिद्ध हुए हैं। अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश में कौशमेमो नहीं देने तथा वितरण पंजी में बी.पी.एल. सं० की प्रविष्ट नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज है। ये सभी आरोप परिकल्पनाओं पर आधारित है। आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा विगत 20 वर्षों से दूकान का संचालन किया जा रहा है। कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत का अगसर आज तक नहीं आया है। परिवार के सदस्यों को कागजात के संबंध में जानकारी नहीं रहने की वजह से उनके द्वारा कागजात नहीं दिखाया गया। विक्रेता के द्वारा सरकार से अनुदानित दर पर प्राप्त सामग्रियों का वितरण उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर पर



निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से किया जाता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विक्रेता के विरुद्ध उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विक्रेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मद्रौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विक्रेता के विरुद्ध उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विक्रेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारणपृच्छा में या अपने आदेश में



	<p>अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में किसी उपभोक्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे लगाए जाने वाले आरोप स्पष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसे में इस मामले को पुनः जाँचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।</p> <p>वाद निष्पादित।</p> <p>लेखापित एवं/संशोधित</p> <p>जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा</p>	
--	---	--

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापक 1053 दिनांक 15/12/14

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप-समर्थता
जिला विधि शाखा, सारण, छपरा।
15/12/14